an>

Title: Regarding Rangarajan Committee Report.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, अभी सी.आर. रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट आई है। वह रिपोर्ट यह कह रही है कि यदि 32 रूपये गांवों में कोई परिवार कमा रहा है, 47 रूपये यदि शहरों में कमा रहा है तो वह गरीबी रेखा के ऊपर है। इस देश में, इस पार्लियामेंट में लगातार जब भी मैं भाषण सुनता हूँ, भाषण करता हूँ तो गरीबों के लिए बातें होती हैं। गरीब के अलावा किसी की बात नहीं होती है। लेकिन गरीबों के साथ कितना बड़ा मजाक होता है, इसका उदाहरण यह है कि पहली बार सन् 1962 में योजना आयोग ने यह निर्णय लिया कि गरीबी रेखा के ऊपर कौन है और नीचे कौन है, इसके बारे में विचार किया जाए। उसको 15 साल लग गए एक कमेटी बनाने में। सन् 1977 में वाई.के. अलघ की एक कमेटी बनी, जिसने यह निर्धारित किया कि यह गरीब है और यह अमीर है। उसके इंप्लिमेंटेशन के लिए एक लकड़वाला कमेटी बनी, सन् 1977 से ले कर 1989 लग गया, लकड़वाला कमेटी को 12 साल लग गए। जब सन् 1993 में उसकी रिपोर्ट आई तो फाइनली सन् 2003-04 में, प्रिसाइज़ली यदि उसको कहें तो सन् 2006 में तेंदुलकर कमेटी बन गई। इसी यूपीए सरकार ने तीन कमेटी और बनाई। तेंदुलकर कमेटी बन गई। इसके बाद अर्जुन सेन गुप्ता की कमेटी बन गई। उसके बाद एन.सी. सक्सैना कमेटी बन गई। जब इन सारी कमेटियों से काम नहीं हुआ तो एक हासिम कमेटी बन गई कि वह अर्बन पूअर को अलग से देखेंगे और रूरल पूअर को अलग से देखेंगे। उन सभी के ऊपर एक सी. रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट बन गई। सी. रंगराजन साहब ने गरीबों के साथ इतना बड़ा मजाक किया। महोदय, उन्हीं सी. रंगराजन साहब ने, जब गैस के प्राइस बढ़ाने की बात आई तो उन्होंने कहा कि 4.2 एम.एम. बीटीयू से, चूंकि मार्केट प्राइस से तय होना है कि अमरीका में गैस का प्राइस कितना होगा, यू.के. में गैस का दाम कितना होगा, इतना ही हिंदुस्तान में होना है तो 4.2 डॉलर से बढ़ा कर उसको 8.4 कर दिया।

सभापति महोदय, हम जो पैट्रोल और डीजल के लिए रोज यहां हंगामा करते हैं, वह कहा जाता है कि मार्केट तय करता है और पैट्रोलियम कंपनियां कहती हैं कि अण्डर रिकवरी होती है। अण्डर रिकवरी यह होती है कि अमरीका में किस रेट में बेचा जा रहा है, यू.के. में किस रेट में बेचा जा रहा है। उस कमेटी को भी रंगराजन साहब ही हैड कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि जब आपको विदेश से ही सब कुछ लेना है और विदेश का एक मापदण्ड है तो सन् 2005 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी कि दुनिया में गरीब कौन है। सन् 2005 की रिपोर्ट है, दुनिया में गरीब वह है, जो कि 1.25 डॉलर से कम कमाता है। यदि 1.25 डॉलर को भी आज की स्थिति में माना जाए तो, मिनिमम 75 रूपये, सन् 2005 का है, यह सन् 2014 में हम लोग बात कर रहे हैं, उस रेट के हिसाब से लगभग 100-110 रूपये के आस-पास वर्ल्ड बैंक पहुंच चुका है, पूरी दुनिया पहुंच चुकी है, यू.एन. का रिज़ॉल्युशन है, तो रंगराजन साहब अमीरों के लिए तो 4.2 से 8.4 हो जाते हैं, लेकिन जब गरीबों की बात आती है तो 32 रूपये और 47 रूपये पर क्यों आते हैं?

सभापति महोदय, मैं इस सरकार से मांग करना चाहूंगा कि आप रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट को जाने दीजिए और यू.एन. में, वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो गरीबों का एक मापदण्ड है कि मिनिमम 100 या 110 रूपये गांव में रहने वाले और 150 रूपये से कम जो शहर में रहने वाले हैं, उनकी एक रेखा निर्धारित कीजिए, जिससे गरीब-गरीब का निर्धारण हो पाए, गरीबों का हम मजाक नहीं उड़ाएं और गरीबों को लगे कि वे भी सम्मान के साथ जिंदगी जीते हैं। मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूँ।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members

Shri Bhartruhari Mahtab,

Shri Arvind Sawant,

Shri Om Prakash Yadav and

Shri Arjun Ram Meghwal are allowed to associate with the issue raised by Shri Nishikant Dubey during '*Zero Hour*'.